

प्रेषक,

झारखंड-सरकार

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय

प्रेषक,

निदेशक,

॥ माध्यमिक शिक्षा ॥ झारखंड, रांची ।

सेवा में,

सचिव,

सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली ।

रांची, दिनांक - 6.10.02

बिषय:-

झारखंड राज्य के अन्तर्गत संचालित निजी विद्यालयों को सखिबखिब
सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से संबंधन हेतु अनापति प्रमाण-पत्र
निर्गत करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त बिषय पर निदेशानुसार कहना है कि मानव संसाधन
विकास विभाग, झारखंड सरकार के द्वारा विचारोपरान्त राज्य के अन्तर्गत संयोजित
संचालित केरला पब्लिक स्कूल, वर्मा माइन्स, जमशेदपुर को सी०बी०एस०ई०, नई
दिल्ली से सम्बन्धता हेतु नीचे अंकित शर्तों एवं बन्धनों के अधीन अनापति प्रमाण-
पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया है ।

1. संस्था एक विद्यालय संचालन नियमावली एक माह के अन्दर तैयार कर विभाग को उपलब्ध करायेगी ।
2. विद्यालय की भूमि टाटा कम्पनी के द्वारा लीज पर दी गई है । चूंकि लीज का मामला विवाराधीन है तथा विद्यालय कार्यरत है । शक्य ऐसे में लीज के संबंध में सक्षम प्राधिकार का जो निर्णय होगा उससे यह अनापति प्रमाण-पत्र प्रभावी होगा ।
3. विद्यालय प्रबन्धन एक सभा भवन छः माह के अन्दर निर्माण कर लेगी ।

उपर्युक्त शर्तों एवं बन्धनों के अतिरिक्त विभागीय आदेश
संख्या-1055 दिनांक -5-9. 2001 के आलोक में निम्नांकित शर्तों एवं बन्धनों
का अनुपालन करना अनिवार्य होगा:-

1. विद्यालय की वार्षिक वृत्त आय 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो ताकि यह प्रमाणित हो सके कि विद्यालय लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से स्थापित नहीं किया गया है । कुल आय का 10 प्रतिशत जो वृत्त होगी उसका उपयोग भी विद्यालय के विकास में किया जायेगा । विद्यालय में कार्यरत सभी कर्मियों को

DIRECTOR



KERALA PUBLIC SCHOOL, BURMAMINES

Principal
Kerala Public School
Burmamines.

- कम से कम राज्य सरकार में कार्यरत समकक्ष कर्मियों को देय वेतन एवं भत्ते के बराबर भुगतान करना होगा ।
2. विधालय को किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जायेगा ।
3. विधालय को बाहरी क्षेत्र में 2११ दो१ एकड़ एवं ग्रामीण क्षेत्र में 4११ चार१ एकड़ भूमि विधालय के नाम से निबंधित या कम से कम 30१ तीस१ बर्षों के निबंधित पट्टा/लीज पर होना चाहिये । यदि भविष्य में जॉचोपरान्त भिन्न स्थिति पाई जायेगी तो अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लेने का अधिकार सरकार को सुरक्षित होगा ।
4. विधालय में हिन्दी भाषा की पढ़ाई अनिवार्य रूप से होनी चाहिये।
5. नामांकन हेतु किसी प्रकार का डीनेशन या कैपिटेशन फीस नहीं लिया जायेगा ।
6. गरीबी रेखा के नीचे के छात्र/छात्राओं का 10 प्रतिशत सीट नामांकन के लिये सुरक्षित होगा साथ ही ~~सत्र~~ सामान्य शुल्क का 50 प्रतिशत शुल्क लिया जायेगा ।
8. ~~सत्र~~ ~~रेखर~~ के ~~सत्र~~ के ~~छत्र~~
7. विधालय का कार्यकलाप राष्ट्र के हित में होना चाहिये । विधार्थियों में राष्ट्रीयता का संचार, नैतिक तथा राज्य के सांस्कृतिकमूल्यों, ऐतिहासिक, भौगोलिक, बैज्ञानिक ज्ञानबर्द्धक, शारीरिक एवं व्यक्तित्व विकास हेतु साकारात्मक प्रयास करना होगा ।
8. विधालय में छात्रों की समुचित संख्या एवं उसके अनुपात में शिक्षक होना चाहिये ।
9. विधालय में नामांकन प्रक्रिया, कर्मियों की संख्या, योग्यता एवं नियुक्ति प्रविधान आदि में समय-समय पर राज्य सरकार समीक्षोपरान्त संशोधन कर सकेगी ।
10. विधालय संचालन हेतु गठित नियमावली के आधार पर गठित शाली निकाय के सदस्यों की कार्यवाधि पूर्ण होने पर सदस्यों की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा ।
11. राज्य /केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न प्रकार के एक्स्टेन्सन प्रोग्राम तथा एन०सी०सी०, एन०एस०एस०स्काउट एवं गार्ड्स आदि को सुचारु रूप से करना होगा ।
12. यदि कोई संस्था पूर्व से किसी बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त हो तो विभागीय परिपत्र ~~सत्र~~ ~~सत्र~~ संख्या-1055 दिनांक -5. 9. 2001 के अनुसार शर्तों का पालन करना होगा अन्यथा अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लेने का सर्वाधिकार राज्य सरकार में सुरक्षित होगा ।

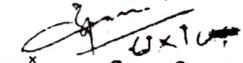

DIRECTOR
KERALA PUBLIC SCHOOL, BURMAMINES

१०५०३०

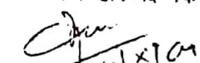

Principal
Kerala Public School
Burmamines.

13. उपर्युक्त शर्तों एवं बन्धनों का अनुपालन न करने की स्थिति में राज्य सरकार को अनापति प्रमाण पत्र रद्द करने का अधिकार होगा ।
14. अनापति प्रमाण-पत्र के लिये विधालय द्वारा तमर्पित कागजातों एवं अभिलेखों का जाली या वास्तविक स्थिति से भिन्न पाया जाय या विधालय द्वारा ~~११*~~ राष्ट्र या राज्य हित के विरुद्ध किया जा रहा हो या ऐसा कार्य जिससे सामाजिक कटुता फैलता हो तो सरकार निर्गत अनापति प्रमाण-पत्र को वापस ले सकती है ।
15. विधालय द्वारा उपर्युक्त शर्तों एवं बन्धनों को अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं इसकी जाँच समय-समय पर मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड के सक्षम पदाधिकारी द्वारा की जायेगी तथा सरकार जब चाहे विधालय संस्था के वित्तीय एवं अकादमिक अनिश्चितताओं की जाँच करा सकेगी और जाँचोपरान्त अनुवर्ती कार्रवाई कर सकेगी ।
16. एतद् बिषयक किसी प्रकार के न्यायिक मामलों का निपटारा ~~प्रश्नप्रश्न~~ माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत होगा ।
17. समय-समय पर लोकहित में सरकार द्वारा विधालय सम्बद्ध संबंधी जो निर्णय लिये जायें उतका अनुपालन करना अनिवार्य होगा अन्यथा शर्तों का उलंघन मानते हुए अनापति प्रमाण-पत्र वापस लेने के साथ-साथ अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी ।

विश्वात्मज


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
झारखंड, रांची ।

ज्ञापक 2516 / रांची, दिनांक - 6.10.07
प्रतिलिपि, संबंधित क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक/संबंधित जिला शिक्षा
पदाधिकारी/संबंधित विधालय के प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ
प्रेषित ।


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
झारखंड, रांची

ज्ञापक 2516 / रांची, दिनांक - 6.10.07
प्रतिलिपि, माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड के आप्त
सचिव/सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड, रांची को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
झारखंड, रांची ।

DIRECTOR


KERALA PUBLIC SCHOOL, BURMAMINES


Kerala Public School
Burmamines.